भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-482

दिनांक 28 नवंबर, 2024 को उत्तरार्थ

उजाला योजना का उद्देश्य

482. श्री भास्कर मुरलीधर भगरेः
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटीलः
श्री निलेश ज्ञानदेव लंकेः
प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ः
श्री बजरंग मनोहर सोनवणेः
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हेः
श्री अमर शरदराव कालेः
श्रीमती सुप्रिया सुलेः
श्री संजय दीना पाटिलः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उजाला योजना के मुख्य उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है और देश में ऊर्जा दक्षता और सतत विकास में यह किस प्रकार योगदान कर रही है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सहित देश में अब तक कुल कितने एलईडी बल्ब वितरित किए गए हैं और अब तक कुल कितनी ऊर्जा की बचत हुई है;

(ग) सरकार इस योजना के अंतर्गत वितरित एलईडी बल्बों की गुणवत्ता और टिकाउपन को किस प्रकार सुनिश्चित करती है और उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों के समाधान के लिए क्या तंत्र है;

(घ) उक्त योजना से घरों में बिजली की खपत के पैटर्न पर क्या प्रभाव पड़ा है और उनके घरेलू बिजली बिलों में कितनी कमी आई है;

(ङ) उक्त योजना के लिए कुल वित्तीय परिव्यय कितना है तथा सरकार द्वारा वित्तपोषण के मानदंड क्या हैं;

(च) क्या सरकार का एलईडी ट्यूबलाइट और पंखों जैसे अन्य ऊर्जा दक्ष उत्पादों को शामिल करने के लिए उक्त योजना का विस्तार करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) ऊर्जा बचत और उपभोक्ता संतुष्टि के संदर्भ में उक्त योजना की सफलता का पता लगाने के लिए अपनाए गए अन्य तंत्रों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) : वर्ष 2015 में शुरू की गई उजाला स्कीम का उद्देश्य घरेलू उपभोक्ताओं को किफायती मूल्य पर ऊर्जा कुशल एलईडी बल्ब उपलब्ध कराना है। एनर्जी एफ़िशिएंसी सर्विसेज़ लिमिटेड (ईईएसएल), विद्युत मंत्रालय के तहत सीपीएसई का एक संयुक्त उद्यम है, जो उजाला के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है।

आज तक, ईईएसएल ने देश भर में लगभग 36.87 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किए हैं, जिससे प्रति वर्ष लगभग 4800 करोड़ किलोवाट घंटा (यूनिट) ऊर्जा की बचत हुई है, प्रति वर्ष 19,153 करोड़ रुपये की मौद्रिक बचत हुई है, 9,586 मेगावाट की अधिकतम मांग से बचा गया है और प्रति वर्ष 3.9 करोड़ टन CO2 उत्सर्जन में कमी आई है।

एलईडी में नगण्य मात्रा में विषाक्त पदार्थ होते हैं, इन्हें निपटान के लिए सुरक्षित बनाया है और पर्यावरण प्रदूषण को कम किया है। कुल मिलाकर, एलईडी एक संधारणीय, ऊर्जा-कुशल प्रकाश समाधान प्रदान करता है जो पर्यावरणीय लक्ष्यों का समर्थन करता है।

(ख) : महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्यों में उजाला स्कीम के अंतर्गत वितरित एलईडी बल्बों का विवरण तथा प्राप्त समग्र वार्षिक ऊर्जा बचत का विवरण अनुबंध पर है।

(ग) : ईईएसएल द्वारा की जाने वाली खरीद एलईडी बल्बों के लिए संगत बीआईएस विनिर्देशों, राष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं की परीक्षण रिपोर्टों के अनुरूप होती है, ताकि एलईडी बल्बों की गुणवत्ता और स्थायित्व सुनिश्चित किया जा सके। इसके अलावा, उपभोक्ता शिकायतों के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर, ईमेल, ऑनलाइन पोर्टल और मोबाइल ऐप जैसी कई व्यवस्थाएं हैं।

(घ) : द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट (टेरी) के स्वतंत्र अध्ययन के अनुसार**,** एलईडी बल्बों के इस्तेमाल से घरों में बिजली का बिल काफी कम हो गया है। इससे एक घर को सालाना औसतन 1300 से 1800 रुपये की बचत हुई।

(ङ) : भारत सरकार ने उजाला स्कीम के लिए कोई बजट आबंटित नहीं किया है। ईईएसएल अपने स्वयं की निधियों (ऋण और इक्विटी) से कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहा है।

(च) : ईईएसएल पहले से ही ऊर्जा कुशल ट्यूब लाइट और ऊर्जा कुशल बीएलडीसी पंखे वितरित कर रहा है। अब तक ईईएसएल ने इस स्कीम के तहत 77 लाख एलईडी ट्यूब लाइट और 24 लाख ऊर्जा कुशल पंखे वितरित किए हैं।

(छ) : उजाला कार्यक्रम की सफलता, ऊर्जा बचत और उपभोक्ता संतुष्टि पर नज़र रखने के लिए तृतीय पक्षकार प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करते हैं और टेरी द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि उजाला स्कीम ने ऊर्जा बचत की दिशा में व्यापक सकारात्मक प्रभाव डाला है।

लो.स.अतारां.प्र.सं.482

अनुबंध

क्रम सं.	राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र	वितरित एलईडी बल्बों की संख्या	वार्षिक ऊर्जा बचत (करोड़ यूनिट में)
1	अंडमान और निकोबार	400,000	5.2
2	आंध्र प्रदेश	2,20,40,227	286.2
3	अरुणाचल प्रदेश	4,99,498	6.5
4	असम	71,92,072	93.4
5	बिहार	1,96,08,609	254.7
6	चंडीगढ़	5,54,283	7.2
7	छत्तीसगढ़	1,08,22,335	140.5
8	दादरा एवं नगर हवेली	1,63,808	2.1
9	दमन और दीव	1,42,623	1.9
10	दिल्ली	1,34,31273	174.4
11	गोवा	10,05,890	13.1
12	गुजरात	4,14,48,713	538.3
13	हरियाणा	1,56,08,119	202.7
14	हिमाचल प्रदेश	86,48,483	112.3
15	जम्मू और कश्मीर	84,86,579	110.2
16	झारखंड	1,36,45,874	177.2
17	कर्नाटक	2,42,64,486	315.1
18	केरल	1,54,29,919	200.4
19	लद्दाख	2,30,630	3.0
20	लक्षद्वीप	2,00,000	2.6
21	मध्य प्रदेश	1,75,74,110	228.2
22	महाराष्ट्र	**2,19,86,569**	**285.5**
23	मणिपुर	2,99,934	3.9
24	मेघालय	4,33,789	5.6
25	मिजोरम	6,15,332	8.0
26	नागालैंड	10,99,038	14.3
27	ओडिशा	5,22,70,570	678.8
28	पुदुचेरी	6,09,251	7.9
29	पंजाब	30,16,739	39.2
30	राजस्थान	1,73,21,034	224.9
31	सिक्किम	1,64,000	2.1
32	तमिलनाडु	43,63,183	56.7
33	तेलंगाना	28,75,082	37.3
34	त्रिपुरा	10,54,437	13.7
35	उत्तर प्रदेश	2,62,95,772	341.5
36	उत्तराखंड	56,73,850	73.7
37	पश्चिम बंगाल	92,29,228	119.9
कुल		**36,87,05,340**	**4788.3**

****